भारत सरकार **लोक सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं.4871**
वाणिज्य विभाग

दिनांक 01 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

आयात प्रशुल्क

4871. डॉ. कलानिधि वीरास्वामी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने, जैसा कि अमरीकी सरकार ने कहा है, इसके के साथ चल रही द्विपक्षीय व्यापार वार्ता के दौरान प्रशुल्क में कटौती करने पर सहमति व्यक्त की है;

(ख) इस प्रकार की प्रशुल्क कटौती से कौन-कौन से विशिष्ट क्षेत्र अथवा सामान प्रभावित होंगे और सरकार किस प्रकार यह सुनिश्चित करने की योजना बना रही है कि इस तरह की कटौती से घरेलू उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े अथवा नौकरी न जाए:

(ग) क्या सरकार ने भारत के व्यापार संतुलन और स्थानीय विनिर्माण क्षेत्र पर इस तरह की प्रशुल्क कटौती के संभावित दीर्घकालिक प्रभाव के बारे में भारतीय उद्योगों और हितधारकों की चिंताओं को ध्यान में रखा है; और

(घ) क्या सरकार ने इन प्रशुल्कों में कटौती के संभावित प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए संबंधित उद्योग निकायों, मजदूर संघों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श किया है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (घ): भारत और अमेरिका ने दिनांक 13 फरवरी, 2025 को एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया, जिसमें आर्थिक संबंधों को गहरा करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। दोनों देश पारस्परिक रूप से लाभकारी, बहु-क्षेत्रीय द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर वार्ता करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके तहत देश बाजार पहुंच बढ़ाने, टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करने, आपूर्ति श्रृंखला एकीकरण बढ़ाने और प्रमुख व्यापार मुद्दों को संतुलित तरीके से द्विपक्षीय रूप से हल करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। भारत सरकार द्विपक्षीय व्यापार समझौते की वार्ता के दौरान उद्योग निकायों सहित सभी हितधारकों के साथ निरंतर परामर्श करती है।

*****